an>

Title: Discussion on the Supplementary Demands for Grants (General) -2016-17 and Demands for Excess Grants (General) - 2013-14 (Discussion Concluded).

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 3, 5, 9,11,12,14 to 20, 22, 24 to 30, 32, 34 to 39, 41 to 44, 46 to 55, 58 to 61, 64, 66, 68, 73 to 75, 79 to 91, 93 to 95 and 97"."

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2014, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 20, 23, 24, 25 and 32.""

...(*Interruptions*)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, सरकार की ओर से माननीय वित्त मंत्री ने जो सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स रखी हैं, उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, मैं कह रही हूँ आप भी इसमें चर्चा करो।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया : महोदया, जो लगभग 59 हज़ार करोड़ रूपये सरकार की ओर से जो एडीशनल डिमांड के स्वरूप में रखी गयी हैं, मुझे लगता है कि मोदी सरकार की जो नीति है, भूमिका है, उसी दिशा में एक और अगला कदम है। इसमें एग्रीकल्चर से ले कर, सर्विस सैक्टर से ले कर सरकार एक-एक कर के जो कदम उठा रही है, फिर वह डी-मोनेटाइज़ेशन हो या काले धन के ऊपर लगाम लगाने की बात हो। ...(व्यवधान) मैं इनमें से एक-दो बातों का विशेषकर कर उल्लेख करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

14.05 hours

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

â€¦(व्यवधान)

उसके पहले आज सुबह माननीय वित्त मंत्री जी ने सर्विस टैक्स के सम्बन्ध में जो एक नोटिफिकेशन हमारे सामने ले किया है, यह क्या है?...(व्यवधान) मुझे लगता है कि जब हम सप्लिमेन्ट्री डिमांड्स की चर्चा करते हैं तो हमारा देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं।...(व्यवधान) एक ओर सिर्फ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, काला धन, काला धन, काला काम है।...(व्यवधान) एक ओर सिर्फ इसकी चर्चा थी...(व्यवधान) और दूसरी ओर इस वीसियस चक्र में से सरकार को कैसे बाहर निकालना है, समाज को कैसे योग्य दिशा में ले जाना है, वह दिशा दिखाने का काम मेरे वित्त मंत्री अरूण जेटली जी कर रहे हैं।...(व्यवधान) जो दो हजार रूपये तक...

HON. SPEAKER: One minute Kirit *ji*.

If I allow him to say something, are you going to start this discussion on Demands for Grants? Give me assurance. Every day you will do all these things. Are you ready for this business?

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the way. Now we have started Demands for Grants. Please. You discuss on this.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपकी उस बात पर जो डिस्कशन की बात है, any time we can start it. मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ। अभी सप्लिमेन्ट्री डिमांड्स पास होने दीजिए। इस बीच कोई दूसरी बात नहीं होगी।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप इस डिस्कशन पर एग्री हैं?

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, नियम 184 में चर्चा कराने वाली बात है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप अभी सप्लिमेन्ट्री डिमांड पर डिस्कशन करोगे?

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह बात अभी नहीं उठानी है। I am sorry. Yes, Kirit *ji*, you continue.

â€¦(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया : महोदया, मेरे जो सहयोगी मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, वे कभी-कभी चर्चा में यह कहते हैं कि काला धन एक शाप है।...(व्यवधान) कभी-कभी वे आँकड़े हमारे सामने रखते हैं कि 35 लाख करोड़ का काला धन इस देश में है।...(व्यवधान) एक सहजता से प्रश्न आज का हमारा विद्यार्थी पूछता है कि मोदी जी की सरकार को कितने महीने हुए हैं?...(व्यवधान) 24 महीने हुए हैं।...(व्यवधान)

14.07 hours

(*At this stage, Shrimati Arpita Ghosh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

काला धन जो 35 लाख करोड़ इकट्ठा हुआ, क्या वह मोदी के कारण हुआ है?...(व्यवधान) क्या भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. के शासन के कारण हुआ है?...(व्यवधान) यह जो शाप है, वह 60 साल की सरकार का शाप है।...(व्यवधान) इस शाप से मुक्त करने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक, काले धन पर एसआईटी से लेकर आज डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है। एक ओर हम काले धन से मुक्ति चाहते हैं और दूसरी ओर नया काला धन जनरेट न हो, जो गए अनेक दिनों से चर्चा चल रही है, आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर दो हजार रूपये तक सर्विस टैक्स से मुक्ति, यानी सरकार का कमिटमेंट है कि वी वान्ट टू गो फोर कैश लेस।...(व्यवधान) कैश एंड टैक्स इवेशन।...(व्यवधान) एक ऐसा सम्बन्ध हो चुका है और इसके लिए जब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है, वैसे ही मोदी जी का नाम लेते हैं।...(व्यवधान) टाइम्स का जो सर्वे हुआ, उसमें विश्व के टॉप तीन-चार नेताओं में जब मेरे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम आता है तो मुझे उनके ऊपर गर्व, अभिमान महसूस होता है।...(व्यवधान) आज तक कितनी बार इस प्रकार हिन्दुस्तान के नेताओं का नाम आया।...(व्यवधान) वह नाम क्यों आया, क्योंकि एक ओर वह काला धन और दूसरी ओर काला धन जनरेट नहीं होने देना है।...(व्यवधान) इन सप्लिमेन्ट्री डिमांड्स में माननीय वित्त मंत्री जी ने नगर विकास विभाग की सप्लिमेन्ट्री डिमांड्स में रखते समय मेट्रो के बारे में उल्लेख किया है, मुम्बई मेट्रो के बारे में उल्लेख किया है।...(व्यवधान) मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस सप्लिमेन्ट्री डिमांड्स में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपने एडीशनल धन का, एडीशनल एक्सपेन्डिचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए परमीशन माँगी है, मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूँ।...(व्यवधान) मैं मुम्बई का उदाहरण देता हूँ। मुम्बई में पिछले 15 वर्ष से मुम्बई मेट्रो की सिर्फ चर्चा होती थी।...(व्यवधान) सिर्फ चर्चा, चर्चा और चर्चा होती थी।...(व्यवधान) मोदी सरकार आई, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस बने और पिछले एक साल के अन्दर मुम्बई में पूरे मेट्रो की कनेक्टिविटी हो गई।...(व्यवधान) एक लाख करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट को मोदी सरकार और फड़नवीस सरकार ने मान्यता दे दी।...(व्यवधान) जापान सरकार और उसका फाइनैंशियल कार्पोरेशन हमें 1 परसेंट के रेट से इंटरस्ट पर लोन देना चाहता है। जो मैट्रो वाली बात है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो इस प्रकार का इनफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट इनफ्रास्ट्रक्चर है, उसके प्रति और अधिक ध्यान हमें देना चाहिए। ...(व्यवधान)

मैं एक और विषय की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसे आपने क्रैडिट कार्ड और डैबिट कार्ड की बात की, उसी प्रकार से कैशलैस इकोनॉमी की दृष्टि से आने वाले बजट में इंसैंटिव्स के बारे में विचार करना चाहिए कि हम कैसे लोगों को एनकरेज करें। ...(व्यवधान) अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि जैसे जी.एस.टी. की बात है, वित्त मंत्री ने अनेक महीनों से जीएसटी के लिए भी कुछ एडीशनल पैसे मांगे हैं। जीएसटी जल्द से जल्द इंप्लीमैंट हो, इसके लिए सारी संसद और सारे प्रदेश की सरकारों को इसमें सहयोग करना चाहिए।

मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Madam, I rise to support the passing of Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2016-17 for an amount of Rs. 59,978.29 crore. Madam, the hon. Minister had requested for Second Supplementary Demands for Grants. With regard to all these Demands, they are pertaining to different ministries. I am concerned particularly with Demand No. 32 which is with regard to transfer to the States. ...(*Interruptions*) In this Demand, the hon. Minister has specified some amount. My State, that is the State of Telangana, is a new State. With regard to the transfer of fund to the State, the Ministry is asking for utility certificate for every quarter. Ours is a new State. We are facing some problems. I would like the hon. Minister to consider that while releasing these Grants, let it be on a yearly basis instead of quarterly basis. ...(*Interruptions*)

At the same time, the State of Telangana has requested the hon. National Highways Minister to grant funds for laying of the new highways because the State of Telangana was having less number of highways than the national average number of highways. So, the Chief Minister of Telangana, hon. K. Chandrasekhara Rao had personally met the hon. Minister for release of some grants....(*Interruptions*) So, in the event of having release of some grants, let the hon. Finance Minister release it to the Ministry of National Highways so that the Ministry will help the State of Telangana in the coming days and I support this Bill and I request all the Members to pass this Bill.

श्री अभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आज अपनी ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है।

अध्यक्ष महोदया, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स मूलतः दो वजहों से सदन के सामने आती हैं। जब ऑथराइज़ अमाउंट सफीशिऐंट नहीं रह जाता या फिर एडीशनल एक्सपैंडीचर की ज़रूरत महसूस होती है। मैं आज आपके सामने सदन को बताना चाहता हूँ कि इन सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स के माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की राशि का निर्धारण इस लोक सभा के सामने रखा है, जिसके तहत लगभग 35,171 करोड़ रुपये का नैट कैश आउटगो, जिसका मतलब है कि इनक्रीज़ इन नैट स्पैंडिंग इस देश के सामने होगी। लगभग 24805 करोड़ रुपये की राशि का जो व्यय है, वह डिपार्टमैंट और मिनिस्ट्रीज़ की जो सेविंग्ज़ हैं, या फिर जो रिसीट्स और रिकवरी की राशि है, उसके माध्यम से पूरा किया जाएगा। ये डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स एक महत्वपूर्ण दौर पर इस देश के सामने आई हैं। एक तरफ जहाँ पिछले कई महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट देखने को मिले हैं। चाहे वह यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के अलग होने की वज़ह से आई अनिश्चितता हो या फिर लगातार चीन में आ रहे स्लो-डाउन की वज़ह से वैश्विक कंजम्पशन नीचे गया हो या फिर अमेरिका में फेड के रेट्स आने वाले समय में क्या होंगे, उसकी वज़ह से हो, कुल मिलाकर पूरे विश्व में, चाहे वह इंवेस्टमेंट हो या प्राइवेट कंजम्पशन हो, उसमें कमी आई है।...(व्यवधान) लेकिन, मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को, प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था सितम्बर के क्वार्टर में 7.3औ की रफ्तार से आगे बढ़ी है और पूरा देश कहीं न कहीं आज भारत की सरकार के द्वारा हो रहे स्पेंडिंग के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा है।...(व्यवधान)

आदरणीय महोदया, पिछले कुछ महीनों में कई महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाए हैं, लेकिन जो सबसे बोल्ड और ऐतिहासिक कदम इस सरकार ने उठाया है, वह यह है कि काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और अघोषित आय से हो रहे इस देश के नुकसान में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए 500 रुपए और एक हजार रुपए के नोट को परिवर्तित करने का एक साहसिक निर्णय आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लिया है।...(व्यवधान) मैं पूरे देश की जनता की तरफ से आदरणीय वित्त मंत्री जी को और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

महोदया, यह देखने में आता है कि जब भी राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता होती है, यह एक चुनौती होती है तो यह एक अवसर भी होता है कि हम ऐसी चुनौती को अवसर में बदल कर समय के साथ ताल से ताल मिलाकर अपने देश को एक बेहतर अर्थव्यवस्था के रूप में, एक सफल लोकतंत्र के रूप में आगे लेकर जाएं।...(व्यवधान) आज पूरा विश्व भारत देश की ओर उम्मीद भरी निगाह से देख

रहा है कि भारत में आ रहे इस महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव का आने वाले समय में क्या सकारात्मक प्रभाव होगा?...(व्यवधान) मैं फिर से आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज इस देश की 65 प्रतिशत युवा आबादी अपने भविष्य के सुनहरे सपनों को साकार करने का इरादा लेकर तैयार खड़ी है और आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जिस तरीके से मेक-इन-इंडिया, स्किल इंडिया, एप्रैन्टिस एक्ट के माध्यम से रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने का वातावरण निर्माण किया है, निश्चित रूप से यह देश उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।...(व्यवधान)

महोदया, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं।...(व्यवधान) राजनांदगांव जिला ग्रामीण परिस्थिति का जिला है।...(व्यवधान) आज यह महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है कि जहां पहले लोग सरकार से रोटी, कपड़ा और मकान की अपेक्षा करते थे, आज इन अपेक्षाओं में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है।...(व्यवधान) रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क की सुविधा, हर गांव में बिजली की सुविधा, हर खेत में पानी की सुविधा और इन तमाम योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश में नई जन अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का और अपने भविष्य के प्रति मजबूत इरादों का सृजन किया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इन सारी योजनाओं के पीछे इस सरकार की बेहतर क्रियाशीलता दिखाई देती है कि इस डिमांड्स-फॉर-ग्रांट्स में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का नया आउट-ले घोषित करने की मांग की गयी है।...(व्यवधान) यह जो परिवर्तन है, इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी सिर्फ सरकार की मांग या सरकार से अपेक्षाओं का एक प्रतिबिम्ब नहीं है, बल्कि इस देश में जो शायद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, वह जन अपेक्षाओं से आगे बढ़ कर जन आदर्शों की तरफ इस देश की जनता जा रही है, उस दिशा में परिवर्तन हुआ है।...(व्यवधान) जन-अपेक्षाओं से आगे बढ़ कर इस देश की जन शक्ति का एक सकारात्मक दिशा में निराकरण आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किया है।...(व्यवधान) उसके सिर्फ तीन उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा।...(व्यवधान)

महोदया, इस देश में प्रधान मंत्री जी के एक आह्वान पर डेढ़ करोड़ लोगों ने अपने गैस सिलेण्डर की सब्सिडी को स्वेच्छा से, गरीबों की सेवा में सरकार उसका उपयोग कर सके, इसके लिए छोड़ा है।...(व्यवधान) यह दर्शाता है कि इस देश की जनता इसके लिए तैयार है, सिर्फ मांग करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी समझ कर, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी तैयार है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान की पहल एक सरकारी पहल न होकर, हर मां, हर बेटी की दिल से निकली दुआ बन कर एक जन आंदोलन, इस भारत देश के स्वाभिमान का जन आंदोलन बन कर आगे बढ़ी है।...(व्यवधान) यह दर्शाता है कि यह देश सिर्फ मांग पर नहीं, बल्कि जन-आदर्शों को लेकर, जन-शक्ति को लेकर आगे बढ़ रहा है। ...(व्यवधान)

अंत में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज जिसे न सिर्फ हम, बल्कि शायद चाइना हो या दुनिया के अन्य देश हों, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव देखते हैं, पांच सौ रुपए और एक हजार रुपए के नोटों को बदलने की जो योजना है, उसमें इस देश की जनता ने सरकार के साथ खड़े रहने का फैसला किया है। ...(व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहने का फैसला किया है और यह फैसला किया है कि भारत के पुनर्निर्माण में इस देश की जनता की भागीदारी सकारात्मक रूप से होगी। ...(व्यवधान)

जन-आदर्शों को प्रणाम करते हुए, मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी के इस प्रपोजल का समर्थन करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। ...(व्यवधान)

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you, Madam Speaker, for giving me an opportunity to participate in the discussion on Supplementary Demands for Grants on behalf of our party Biju Janata Dal. While on the subject, it is important for me to touch upon the issue of demonetization which has affected the whole country and virtually derailed the functioning of the Parliament. ...(*Interruptions*)

Speaker Madam, our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik has all along supported the move of demonetization which is against black money and we all stand here to support that. But if we go to the ground, we find that there is a very difficult situation. It is a kind of warlike situation in the country. It is not a war on LoC but a war in the financial sector. It is important that we all have to come together irrespective of party politics, join hands to see that the economic difficulty which the people of our country are facing is handled. No other consideration must come and play over here. This is a kind of an emergency situation. That is why, it is time that we must come together and work hand in hand. ...(*Interruptions*)

Having said that, I would like to come to the issue of economic growth. Today India is the only country in the world which is growing at the highest rate. The growth rate of our economy is 7.6 per cent. I would like to say that though the growth is there, it is not a job-led growth. Almost one million youngsters enter the job market in India every month but we are not able to create jobs. So, I would urge upon the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley, who is sitting over here to take this into consideration while moving the Motion. What is required for us is job and nothing else. ...(*Interruptions*)

Having said that, I will also touch upon the issue of GST, which our Government led by Shri Naveen Patnaik has supported. It is important that GST has to be rolled out from 1st of April, 2017 as has been committed so that repercussion which has arisen out of demonetization can be partly made good by virtue of growth of 9.5 per cent, which the economists believe that GST will result in higher growth in the economy. So, it will be compensated. ...(*Interruptions*)

Then, Madam Speaker, I would like to touch upon the issue of Finance Commission. As per the recommendations of the 14th Finance Commission, the divisible pool share was increased from 32 per cent to 42 per cent. But the State of Odisha remained in loss because the share of divisible pool in respect of Odisha came down from 4.78 per cent to 4.62 per cent amounting to a loss of Rs.4600 crore. I would urge upon the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley to compensate Odisha which we have been striving for. ...(*Interruptions*)

I would also like to urge upon the hon. Finance Minister not to make any budgetary provision for supporting the Polavaram Project which we have been advocating in the larger interest of the people of Odisha. Our hon. Chief Minister has repeatedly requested it to the Government of India and we have also been raising this issue in the Parliament. ...(*Interruptions*)

I would like to add just one more point before I conclude. Health sector in our country has been passing through one of the most difficult times. There are several studies which say that if the per capita income of the people of our country increases by one per cent, the private expenditure on the health care goes up by 1.4 per cent meaning thereby that we Indians are becoming poor with every passing day because of the difficulty in the health sector. So, I would urge upon the Union Government to make higher budgetary provision for the health sector so that whatever assurances in respect of improvement in health sector were given by the Government when it came to power in 2014, are addressed ...(*Interruptions*)

With these words, I thank you and support the Supplementary Demands for Grants. ...(*Interruptions*)

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। डिमोनेटाइजेशन एक विषय है जिस पर सभी चर्चा कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग साढ़े बारह लाख करोड़ रुपये भारत सरकार के खजाने में आया है। किसानों के ऊपर कॉआपोरटिव सेक्टर का तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, अगर सही में सरकार चाहती है कि किसान का दर्द दूर हो तो उस अतिरिक्त पैसे से किसानों का कर्ज माफ करने का काम करें। पिछले दिनों प्रश्न काल में यह मुद्दा उठा था कि स्पोर्टस इफ्रास्ट्रक्चर देश में डैवलप करने की जरूरत है, एक्सेस ग्रांट्स में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स के लिए एडीशनल ग्रांट्स की बात नहीं की गई। केन्द्र सरकार एक तरफ कहती है कि 2020, 2024 और 2028 ओलंपिक के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जब वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाला था तो 200 करोड़ रुपये एशियाड और कॉम्नवैल्थ के लिए देने का काम किया था। उसी तरीके से सरकार एक स्पेशल कोरपस बनाकर ग्रामीण स्तर पर एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ उनके स्कूलों में इसे डेवलप करने का कोई प्रावधान किया जाए।

महोदया, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है उसमें सतलुज-यमुना लिंक पर दिशा निर्देश दिया है कि केन्द्र सरकार उस नहर का निर्माण करे। माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि सतलुज-यामुना लिंक के निर्माण में जिस पैसे का उपयोग होना है, चाहे वह पैरामिलिट्री के लिए हो या सुदाई या इंजीनियरिंग के लिए हो, आपकी सरकार आने वाले बजट में नहीं, बल्कि इस एक्सेस ग्रांट्स में एक प्रावधान करे, ताकि इस देश में जल के लिए युद्ध न हो, किसी की जान न जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेवारी समझते हुए एडीशनल ग्रांट्स इस बजट के अंदर देने का काम करे, जिसके तहत उस नहर का निर्माण एक साल के अंदर-अंदर हो।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): *Namaste*, Madam. I thank you for giving me this opportunity to speak on Supplementary Demands for Grants. ...(*Interruptions*)

Madam, as earlier speakers have also mentioned, the Parliament has not been functioning now for this whole Session and it is very difficult to have a debate or a discussion in these circumstances, but I would like to say, any way, a few things for those of you who are listening. ...(*Interruptions*)

I want to make only two points. The Government, the Finance Minister has announced a special package for Andhra Pradesh. We have been asking that we should get legislative backing for all the commitments that have been made so far. I just want to ensure that in this discussion also, sufficient funds are available with the Government to fulfil all of the promises made to Andhra Pradesh. That is my first point. ...(*Interruptions*)

My second point is on demonetisation. I know that this is not the subject of this debate, but I just want to make a few points. I know that the cash supply situation has been improving, but it needs to improve more. I think, day by day, there needs to be an improvement, but if we look at it from last week to this week, perceptible difference does not seem to be there. So, we need to see an improvement every week so that we can improve the confidence levels of all the people in this country. ...(*Interruptions*)

Then, there is the issue of service charges for e-payments. Today, many people are not willing to move to the e-payment method because of service charges. The Government has waived the charges for the government transactions. We request the Government to look into it so that the private parties also should waive the transaction charges. It should not be for a period of time, but going forward also, if we have to be in a cashless or less cash economy, digital transactions have to be less costly than cash transactions. ...(*Interruptions*) The question is : How do we bring out the methodology to make that happen? In order to make than happen, digital transactions should be less costly than cash transactions.

There is one other thing, Madam. I have gone to my constituency and I have talked to my people – in the streets, waiting in lines at the vegetable market and in the villages as well. Every single person in this country, right from top to bottom, is going through different levels of inconvenience, but nobody is saying that they do not support this move. Everyone I have spoken to has supported this move. ...(*Interruptions*)

The reason they have supported it is because they are looking forward to a country where the corruption levels go down. That is really what is behind their support of this policy. Therefore, if we see six months from now or one year from now that those corruption levels have not come down, or everything is back to square one, I think the people will not accept that result. So, the result is very important. The intention is very good; inconvenience is acceptable; but the result is very important. If we do not achieve this result, I do not think it is going to be a very good situation. ...(*Interruptions*)

With these words, I would like to support the Supplementary Demands for Grants (General). â€¦ (*Interruptions*)

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Madam, I thank the Chair for giving me an opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants (2016-17). We support these Demands for Grants. ...(*Interruptions*)

There are significant changes in the General Budget (2016-17) presented by the Finance Minister in February this year as it provided impetus to investment in infrastructure, particularly in transport and national highways, and also had some focus on agriculture. There is no doubt that for the last couple of years, India's economy is growing as there have been efforts for freedom and equality for a sustainable economy. ...(*Interruptions*)

Agriculture plays a pivotal role in the economy of a country and better performance of this sector is vital for inclusive growth for a developing country like India. Planned, balanced and harmoniously developing industry and agriculture are essential for employment generation and economic development. However, the agricultural growth, which may have boosted the total GDP growth, seems unlikely to see improvement. Agriculture is lately being badly affected. We did have good monsoon and we were expecting a good crop since agriculture was expanding at about four per cent, but now it is unlikely to happen because of lack of transactions. ...(*Interruptions*)

Farmers who are supposed to grow food for the society and prosper along with it are falling victim to unnatural deaths. Farmers who are spending lakhs of rupees as investment are being left with debts. Natural calamities are adding to their losses and pushing them into difficulties. The Government should waive the loans given to the farmers. ...(*Interruptions*)

As far as healthcare is concerned, there is a huge disparity in the country. It is a matter of shame that India should rank as low as 97 of 118 developing nations in the Global Hunger Index. India also fares poorly on other indices like wasted and stunted children below five and infant mortality. In malnourished and undernourished children, we appear to be a world leader. We should provide enough funds so that we can provide all young children a nutritious breakfast and quality lunch in schools as is being provided in several countries. ...(*Interruptions*)

Madam, it is about three years since Andhra Pradesh has been promised a Special Category status, but the Government is not implementing the assurance given on the floor of this Parliament. The State of Andhra Pradesh, after bifurcation, is facing a financial crunch. The people are agitating and restless. I would request the Government to kindly implement the assurance of granting Special Category status to Andhra Pradesh, as promised in this august House. ...(*Interruptions*)

Also, as promised in this august House during the passage of A.P. Reorganization Act, I would request the Government to set up a Railway Zone at Visakhapatnam. ...(*Interruptions*)

With these words, we support these Supplementary Demands for Grants, Madam. ...(*Interruptions*)

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Madam, I rise to support the Demands for Grants, which have been brought by the hon. Finance Minister before the House. Since it is a constitutional obligation, it has to be passed. On behalf of my Party, Shiv Sena and on my own behalf, I support it. Thank you very much. ...(*Interruptions*)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सप्लीमेंटरी ग्रांट्स जनरल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष जी, जो ग्रांट मांगी गई हैं, इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा ग्रामीण विकास के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि गांवों का विकास हो, इसलिए ग्रामीण विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। एक बड़ी मांग ऊर्जा मंत्री द्वारा की गयी है। ...(व्यवधान) आज देश में पावर की जो स्थिति है ...(व्यवधान) कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा पैदा होती है, तो कुछ राज्यों में पावर की बहुत शार्टेज है। ...(व्यवधान) इसी कारण इस ग्रांट में ऊर्जा विभाग के लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये मांगे गये हैं। ...(व्यवधान) जहां ज्यादा पावर मिल रही है, वहां से पावर ट्रांसफर करके, जिन राज्यों में पावर शार्टेज है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री जी ने जो एक ऐतिहासिक कदम लिया है, उसके लिए मैं उन्हें सबसे अधिक धन्यवाद देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) पिछले ढाई वर्ष में काले धन को रोकने के लिए जो उपाय किये गये हैं, वे पिछले 70 सालों में कभी नहीं लिये गये। ...(व्यवधान) पहली बार मारिशियस के, साइप्रेस के रूट को इस सरकार ने बंद किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : अध्यक्ष महोदया, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। ...(व्यवधान) इसमें कई विषय आ गये हैं, लेकिन मैं किसान होने के नाते किसान के सवाल को यहां रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आजादी के बाद यह पहली सरकार है, जिसने किसानों के लिए अपने बजट में सबसे अधिक धनराशि उपलब्ध करायी है। ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री सिंचाई योजना है। ...(व्यवधान) हर खेत को पानी देने का संकल्प हमारा बहुत पुराना है, जो आज के दिन पूरा हो रहा है। ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है। ...(व्यवधान) किसानों को फसल का नुकसान होता था। ...(व्यवधान) फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों की खुशहाली होगी। ...(व्यवधान) उस फसल बीमा योजना से किसान के नुकसान की भरपाई हो रही है। यह बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने किया है। ...(व्यवधान) जहां तक पशु पालन में दूध के उत्पादन की बढ़ोतरी की बात है। ...(व्यवधान) आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन क्षेत्र है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से कृषि सिंचाई के लिए अलग से बिजली की लाइन लगाने का बड़ा काम भारत सरकार ने किया है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह लड़ाई दूध बनाम दारू की है। ...(व्यवधान) दूध वाले काले धन के विरोध में हैं और दारू वाले काले धन के समर्थन में हैं। ...(व्यवधान) यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...(व्यवधान)

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कई राजनीतिक दलों से जो माननीय सदस्य बोले हैं, मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं। ...(व्यवधान) मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस देश का जो वित्तीय ढांचा है, बजटरी प्रोविजन्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ...(व्यवधान) यू.पी.ए. के कार्यकाल में एक परम्परा थी, जबकि बजट के अंदर बड़ी घोषणा हो जाती थी और साल के अंत में 80 हजार करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये तक काट लिये जाते थे। ...(व्यवधान) जो देश के विकास के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता था, उसकी मात्रा को बहुत सीमित कर दिया जाता था। ...(व्यवधान) पिछले साल पहला वर्ष था ...(व्यवधान) कई वर्षों के बाद, जबकि रिवाइज्ड एस्टीमेट में जो खर्चा सरकार ने किया, वह बजट की योजना से ज्यादा था। ...(व्यवधान) इस बार भी बजट में यह कहा गया था कि प्लान एक्सपेंडीचर साढ़े 5 लाख करोड़ रुपये होगा। ...(व्यवधान) लेकिन पहली और दूसरी सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बाद उसे आलरेडी 5 लाख 95 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। ...(व्यवधान) इस बार विकास के लिए जो पैसा खर्च होना है, वह बजट योजना की तुलना में 8 फीसदी अधिक होने वाला है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, याद रहे कि जब ढाई वर्ष पहले यू.पी.ए. की सरकार थी, तब पूरे विश्व में माना जाता था कि भारत दुनिया की उन पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो कभी भी लुढ़क सकती हैं। ...(व्यवधान) भारत के लिए यह शब्दावली का प्रयोग किया जाता था कि जो फ्रेजाइल फाइव हैं, पांच कमजोर अर्थव्यवस्थायें हैं, हम उनमें पहुंच चुके थे।...(व्यवधान) आज भारत के संबंध में यह कहा जाता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, में यह ब्राइट स्पॉट बन गया है और तीसरे वर्ष लगातार दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, हिन्दुस्तान होने वाला है।...(व्यवधान) इस बजटरी ग्रांट में खर्चा बढ़ाया जा रहा है और लगभग 60 हजार करोड़ रूपया खर्चा होगा, जिसमें से करीब 36 हजार करोड़ रूपया एकस्ट्रा एक्सपेंडीचर होगा।...(व्यवधान) अगर हम उस एकस्ट्रा एक्सपेंडिचर को देखें तो मनरेगा के इतिहास में पहली बार 47 हजार करोड़ रूपये, पहले से चार हजार करोड़ रूपये ज्यादा, मनरेगा में खर्च किया जाएगा। कांग्रेस ने नारे दिये थे, लेकिन खर्चा कभी नहीं किया था।...(व्यवधान) उसके अतिरिक्त 'फसल बीमा योजना', किसान के लिए प्राइस स्टैब्लाइजेशन फंड, 'स्वच्छ भारत', स्वास्थ्य संबंधी अन्य योजनाओं के अंदर यह खर्च किया जायेगा।...(व्यवधान)

जहां तक काले धन का सवाल है, कांग्रेस को वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक शासन में रहने का अवसर मिला था।...(व्यवधान) मैं आज उनको चुनौती देता हूं कि दस साल के शासन में एक कदम वह गिना दें, जो काले धन के खिलाफ उनकी सरकार ने लिया है।...(व्यवधान) आज यह नारा लगाते हैं कि केन्द्र सरकार ने 50 फीसदी टैक्स की सुविधा देकर लोगों को एक मौका दिया है।...(व्यवधान) यह 50 फीसदी नहीं है, उसमें से भी जो आधा बचेगा, 25 फीसदी चार साल के लिए सरकार रखेगी।...(व्यवधान) अगर उसका ब्याज भी जोड़ लिया जाये तो यह लगभग 65 प्रतिशत पड़ेगा।...(व्यवधान) लेकिन, जब इनकी सरकार थी, वह वी.डी.आई.एस. लेकर आई थी और वर्ष 1997 में यह कहा कि असैट की जो कीमत होगी, वह वर्ष 1987 की मानी जायेगी तो इफैक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन ब्लैकमनी पर केवल आठ प्रतिशत था। ...(व्यवधान) Eight per cent was the effective rate of taxation under that scheme. आज इनको 65 प्रतिशत भी बहुत कम

लग रहा है, लेकिन वर्ष 1997 में आठ प्रतिशत इफैक्टिव रेट के ऊपर ये योजना लेकर आये थे।...(व्यवधान)

डिमौनेटाइजेशन, जो सरकार ने 08 नवम्बर, 2016 को कदम उठाया था, उसके तहत मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 30 दिसम्बर, 2016 तक हम इस स्थिति को अधिकतर सामान्य करेंगे।...(व्यवधान) लोगों को जो तकलीफ है, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ...(व्यवधान) हर रोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मात्रा में करैंसी बाजार में डालता है, बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से डालता है और एक प्रयास है कि अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था लेस कैश हो और उसके साथ-साथ डिजिटलाइज हो, इसका प्रयास भी बड़े पैमाने पर चल रहा है।...(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इन सप्लिमेंट्री ग्रांट्स को पारित किया जाये। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants-Second Batch (General) for 2016-17 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14 to 20, 22, 24 to 30, 32, 34 to 39, 41 to 44, 46 to 55, 58 to 61, 64, 66, 68, 73 to 75, 79 to 91, 93 to 95 and 97."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Supplementary Demands for Grants-Second Batch (General) for 2016-17 are passed.

I shall now put the Demands for Excess Grants (General) for 2013-14 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March 2014, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 20, 23, 24, 25 and 32."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Supplementary Demands for Grants (General) for 2013-14 are passed.